



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2015/चैत्र 17, 1937

No. 81]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2015/CHAITRA 17, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2015

(निर्णायक समीक्षा जाँच)

विषय : जापान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

सं. 15/29/2014-डीजीएडी.—यतः 1995 में और उसके बाद यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने 03.09.2009 को जापान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जाँच की भी शुरूआत की और प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम 16.02.2010 को जारी किए गए थे। दिनांक 9.04.2010 को अनंतिम शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी ने 19.01.2011 को अपने अंतिम जाँच परिणाम जारी किए जिसमें निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई और दिनांक 18.04.2011 की सीमाशुल्क अधिसूचना द्वारा 9.04.2010 से 5 वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था। इस शुल्क की अवधि दिनांक **8.04.2015** को समाप्त हो जाएगी।

और यतः निर्णायक समीक्षा की शुरूआत के लिए अनुरोध

2. यतः समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो उसे लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष बीत जाने पर लागू नहीं रहेगा। संबंधित नियमों में यह अपेक्षित है कि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करें और यदि वह उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट हों कि ऐसे शुल्क को लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार से उसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। उक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी उपाय के अवधि समाप्त होने की तारीख से पहले तर्कसंगत अवधि के भीतर

घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा कर सकते हैं कि क्या शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है।

3. और यतः एसीटोन के घरेलू उत्पादकों अर्थात् मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और मै. एसआई ग्रुप इंडिया द्वारा अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक याचिका दायर की गई है जिसमें उक्त देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तु के पाटन के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है और जापान और थाईलैंड (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की राशि को जारी रखने और उसे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

ख. समीक्षा के लिए आधार

5. लागू पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने का अनुरोध इन कारणों पर आधारित है कि थाईलैंड से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है और उपाय के समाप्त होने के परिणामस्वरूप पाटन के जारी रहने और उसके और अधिक हो जाने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है। आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि पाटनरोधी शुल्क लागू है, थाईलैंड के निर्यातकों ने भारतीय बाजार में वस्तुओं का पाटन जारी रखा है यद्यपि लागू पाटनरोधी शुल्क की वजह से उसकी मात्रा में कमी आई है। अतः यदि वर्तमान पाटनरोधी को हटाया जाता है तो पाटन और तेज हो जाएगा।

6. यद्यपि जापान से संबद्ध वस्तु का कोई वर्तमान आयात नहीं है तथापि, याचिकाकर्ता ने बताया है कि संबद्ध वस्तु के निर्यातों की मात्रा और वह कीमत जिस पर तीसरे देशों को उनका निर्यात किया गया है, पर विचार करते हुए उस देश से पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना है और यदि उस देश के विरुद्ध शुल्कों को हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति और अधिक हो जाएगी।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. दिनांक 19 जनवरी, 2011 की एसीटोन की मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार बताया गया था:

"विचाराधीन उत्पाद एसीटोन है। एसीटोन एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसे डिमिथाइल किटोन के रूप में भी जाना जाता है और उसका उपयोग बल्क भेषजों, कृषि रसायनों, रंजक पदार्थों, कतिपय विस्फोटकों और निम्नवर्ती रसायनों के विनिर्माण में किया जाता है। एसीटोन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत उपशीर्ष सं0 29141100 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। यह एक मूल कार्बनिक रसायन है जो एकल ग्रेड में उत्पादित होता है। यह एक रंगहीन द्रव है। इसका प्रयोग अनेक कार्बनिक सिंथेसिस में विलायक या एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में किया जाता है। एसीटोन का विशिष्ट रूप से उपयोग आइसोफोरोन, डायासिटोन, अल्कोहल, मिथाइल मेथाक्रीलेट और बिस्फेनोल के विनिर्माण में होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग कतिपय रबड़ रसायनों या आक्सी एसीथाइलीन सेल्यूलोज एसीटेट के विनिर्माण में भी होता है और पेंट/कोटिंग के विनिर्माण में विलायक के रूप में होता है। इसका विपणन दो रूपों - खुला बल्क और पैकड में होता है।"

7. वर्तमान जाँच के निर्णायक समीक्षा जाँच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा कि मूल जाँच में परिभाषित किया गया है।

8. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि उनके द्वारा उत्पादित एसीटोन और संबद्ध देश से आयातित एसीटोन भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से समान वस्तुएं हैं। आयातित उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इनका एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं।

9. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत उपशीर्ष सं0 29141100 के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

घ. घरेलू उद्योग

10. निर्णायक समीक्षा के लिए याचिका मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और मै. एसआई ग्रुप इंडिया लि. द्वारा दायर की गई है। यह नोट किया जाता है कि मै. एसआई ग्रुप ने आवद्ध खपत के लिए शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत संबद्ध देशों से इतर देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। अतः प्राधिकारी ने एसआई ग्रुप इंडिया लि. को घरेलू उद्योग के घटक के रूप में पात्र माना है।

ङ. शामिल देश

11. जापान और थाईलैंड के विरुद्ध शुल्क लागू हैं। दोनों देशों से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णायक समीक्षा में जापान और थाईलैंड दोनों देश शामिल होंगे।

ड. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

12. समीक्षा की जरूरत को सही बताते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार एतद्वारा इस बात की समीक्षा करने के लिए समीक्षा की शुरुआत करते हैं कि क्या एसीटोन के लिए दिनांक 18.04.2010 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 36/2011- सीमाशुल्क द्वारा लागू शुल्क को हटाये जाने से थाईलैंड और जापान से संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है और संबद्ध वस्तु के विरुद्ध लागू निश्चयात्मक शुल्क को लागू रखने की जरूरत है।

च. प्रक्रिया

13. इस जाँच से यह निर्धारित होगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है। प्राधिकारी इस बात की जाँच करेंगे कि क्या पाटन की क्षतिपूर्ति करने के लिए शुल्क लागू रखना आवश्यक है और क्या यदि शुल्क को हटाया या उसमें बदलाव या ये दोनों किया जाता है तो क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(i) इस समीक्षा में थाईलैंड और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के लिए दिनांक 19.01.2011 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना के सभी पहलू शामिल हैं।

(ii) वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) के रूप में अप्रैल, 2013 से सितम्बर, 2014 तक की जाँच की अवधि है। तथापि, क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013 और जाँच अवधि के आंकड़ों पर विचार किया जाएगा।

(iii) संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

छ. सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****कमरा सं. 15, चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,****नई दिल्ली-110001**

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

ज. समय-सीमा

16. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

झ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप से अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां सॉफ्ट प्रतियों के साथ, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे.के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2015

(Sunset Review Investigation)

Subject: Initiation of Sunset Review of the antidumping duty in force on imports of Acetone originating in or exported from Japan and Thailand.

F. No. 15/29/2014-DGAD – Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an antidumping investigation against import of Acetone originating in or exported from Japan and Thailand on 03.09.2009 and preliminary findings were issued by the Authority on 16.2.2010. Provisional duties were imposed on 09.04.2010. The Authority issued its final findings on 19.1.2011 recommending imposition of definitive duties and duties were imposed vide customs notification dated 18.4.2011 for a period of 5 years from 09.04.2010. The duties shall expire on 08.04.2015.

A. Request for initiation of Sunset Review

2. Whereas in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the Rules made there under, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition. The Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of anti dumping duty and if it is satisfied, on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its withdrawal. Notwithstanding the above

provision the authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And Whereas a petition has been filed by the domestic producers of Acetone, i.e., M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and M/s SI Group India Ltd. (hereinafter referred to as petitioners) in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods, originating in or exported from the above countries and consequent injury to the domestic industry and requesting for initiating a sunset review investigation for continuation and enhancement of the quantum of anti-dumping duty in force on imports of Acetone (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from Japan and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries).

B. Grounds for review

4. The request is for continuation of the antidumping duties in force based on the grounds that dumping of the subject goods has continued from Thailand and the expiry of the measure would be likely to result in continuation and intensification of dumping from that country and consequent injury to the domestic industry. The applicants have, inter-alia, claimed that in spite of the fact that antidumping duty is in force, the exporters from Thailand have continued to dump the subject goods in the Indian market, though the volume has declined in view of the antidumping duty in force. Therefore, dumping would be intensified if the present antidumping duty be revoked.

5. Though there is no current import of the subject goods from Japan, the petitioner has submitted that there is a likelihood of recurrence of dumping from that country, considering the volume of export of the subject goods and price at which they are exported to the third countries, and that would intensify the injury to the domestic industry, if the duties are revoked against that country.

C. Product under consideration and like Article

6. The product under consideration in the Final Findings of the original investigation of Acetone dated 19th January, 2011 was described as follows:

“The product under consideration is ‘Acetone’. The Acetone is organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agro chemicals, dye stuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under sub-heading 29141100. It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colourless liquid. It is used in numerous organic syntheses either as a solvent or as an intermediate. Acetone is specifically used in manufacture of Isophoron, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bisphenol A. Besides this it is used in manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acethylene Cellulose Acetate and also a solvent in the manufacture of Paints/Coatings. It is marketed in two forms- loose bulk and packed.”

7. Present investigation being a sunset review investigation, the product under consideration would remain the same as has been defined in the original investigation.

8. Petitioners have submitted that the Acetone produced by them are like article to Acetone imported from the subject countries in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The imported products and the domestically produced goods are technically and commercially substitutable, and consumers use them interchangeably.

9. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Custom Tariff Act under the subheadings 2914 11 00.

D. Domestic industry

10. The petition for the sunset review has been filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and M/s SI Group India Ltd. It is noted that M/s SI Group has imported the subject goods from countries other than the subject countries under duty exemption scheme for captive consumption. The Authority has, therefore, considered SI Group India Ltd. as eligible to be a constituent of the domestic industry.

E. Countries involved

11. The duties are in force against Japan and Thailand. In view of the prima facie evidence of continuation or recurrence of dumping from both the countries and consequent injury provided by the petitioners, the sunset review will cover both Thailand and Japan.

F. Initiation of Sunset Review

12. Having satisfied itself on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry, substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9 a (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review whether revocation of the duty, imposed Customs Notification No. 36/2011- Customs dated 18.04.2011 on Acetone, shall lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods from Thailand and

Japan and continuation or recurrence of injury to the domestic industry and need for continued imposition of the definitive duty in force against the subject goods.

G. Procedure

13. The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- (i) The review will cover all aspects of Final Finding Notification dated 19.01.2011 for Acetone originating in or exported from Thailand and Japan;
- (ii) The period of investigation for the purpose of the present review is from April 2013 – September, 2014 as the period of investigation (POI). However, for the purpose of analyzing injury, the data of 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI shall be considered;
- (iii) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

H. Submission of Information

14. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 15, 4th Floor Jeevan Tara Building, Parliament Street
New Delhi-110001

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

I. Time Limits

16. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

J. Submission of information on confidential basis

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential, version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential

information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of public file

24. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

L. Non-cooperation

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority